पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

राम कृष्ण कुमार उर्फ नन्हकू पांडे

बनाम

गीता देवी

2016 की विविध अपील सं.95

7 अगस्त 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. बजंथरी और माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पंडित सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या पारिवारिक न्यायालय द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर खारिज किए गए तलाक के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है?

2. क्या प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, पटना का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

हेडनोट्स

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-धारा 13-तलाक-क्रूरता और परित्याग के आधार पर-अपीलकर्ता का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार उत्तरदाता के साथ संपन्न हुआ था-विवाह विधिवत संपन्न हुआ था; हालांकि, विवाह से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था-तलाक की याचिका विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई थी क्योंकि अपीलकर्ता ने तलाक के लिए अपना मामला नहीं बनाया था।

निर्णय: अपीलकर्ता-पति ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर उत्तरदाता द्वारा उसके और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति किए गए क्रूर व्यवहार को साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार अपीलकर्ता-पति पर है - जहाँ तक परित्याग के आधार का संबंध है, अपीलकर्ता का मामला यह है कि उत्तरदाता के साथ अपीलकर्ता का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई याचिका भी दायर नहीं की है, जिससे यह तथ्य और भी सिद्ध होता है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिससे तलाक याचिका में उसके आरोप के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है - अपीलकर्ता-पति यह साबित करने में विफल रहा है कि

उत्तरदाता-पत्नी ने स्वयं अपीलकर्ता पति को त्याग दिया है - अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि और अवैधता नहीं है - अपील खारिज की जाती है।

(पैराग्राफ 14, 16, 19, 20)

न्याय दृष्टान्त

समर घोष बनाम जया घोष, **2007 (4) एससीसी 511**; नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारैह दास्ताने, **एआईआर 1975, 1534**; जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी, **(2008) 10 एससीसी 497—पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

मुख्य शब्दों की सूची

तलाक; विवाह; विवाह विच्छेद; क्रूरता और परित्याग; विवाह विच्छेद की डिक्री

प्रकरण से उत्पन्न

वैवाहिक प्रकरण संख्या 150/2014 में विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 19.11.2015 के निर्णय एवं डिक्री से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के लिए : श्री शिवेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री पुरूषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता; श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता; श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता; श्री कुमार समीर, अधिवक्ता.

उत्तरदाता के लिए: श्री परशुराम सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर जिनके द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की विविध अपील सं.95

==========

राम कृष्ण कुमार उर्फ़ नन्हकू पांडे, पिता-सत्यनारायण पांडे, गाँव पोस्ट-शमशेरनगर, थाना-दाऊदनगर, जिला-औरंगाबाद के निवासी

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

गीता देवी, पति- राम कृष्ण कुमार उर्फ़ नन्हकू पांडे, पिता-राम कृपाल शर्मा, गाँव-कोडरा, डाकघर-कोडरा, थाना-पालीगंज, जिला-पटना की निवासी

.... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति:

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री शिवेंद्र प्रसाद सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री पुरुषोत्तम शर्मा, अधिवक्ता
श्री गौरव कुमार, अधिवक्ता
श्री मुकुंद कुमार, अधिवक्ता
श्री कुमार समीर, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री परशुराम सिंह, अधिवक्ता

==========

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

सी ए वी निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

दिनांक : 07-08-2025

पक्षों को सुना।

2. अपीलकर्ता ने इस अपील में, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद द्वारा वैवाहिक प्रकरण संख्या 150/2014 में पारित दिनांक 19.11.2015 के

निर्णय और डिक्री के विरुद्ध अपील की है, जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 अधिनियम') की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका, जिसमें तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद की मांग की गई थी, खारिज कर दी गई है।

3. संक्षेप में, अपीलकर्ता का विवाह उत्तरदाता के साथ 04.05.1984 को हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार संपन्न हुआ। विवाह विधिवत संपन्न हुआ; हालाँकि, इस विवाह से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई।

4. धारा 13 अधिनियम के तहत दायर अपनी याचिका में अपीलकर्ता का तर्क यह था कि अपीलकर्ता का विवाह 04.05.1984 को गीता देवी (उत्तरदाता) के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसने अलग घर के लिए झगड़ा शुरू कर दिया क्योंकि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी। उत्तरदाता एक झगड़ालू महिला थी और अपीलकर्ता या ससुराल के अन्य सदस्यों के साथ उसके कभी अच्छे संबंध नहीं रहे। इसके अलावा, अपीलकर्ता का मामला यह है कि अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए, उसने उत्तरदाता के साथ दूसरे घर में अलग रहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने फिर से अपीलकर्ता से उसकी संपत्ति अपने पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया। अपीलकर्ता को विवाह के बाहर कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपना पैसा खर्च किया और कई डॉक्टरों से परामर्श किया। उत्तरदाता ने राज्य महिला आयोग, पटना के समक्ष मामला संख्या 257/2013 के तहत शिकायत दर्ज कराई है और उसने अपीलकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 498(ए) और 379 के तहत दाउदनगर थाना मामला संख्या 336/2013 भी दर्ज कराया है, जिसमें अपीलकर्ता जमानत पर है। अपीलकर्ता और उत्तरदाता के बीच वैवाहिक संबंध पहले ही पूरी तरह से टूट चुके हैं और उनके वैवाहिक जीवन के बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए, दोनों पक्षों के बीच विवाह विच्छेद

हेतु तलाक की याचिका दायर की गई है।

5. उत्तरदाता-पत्नी उपस्थित हुई और अपना लिखित बयान दाखिल किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता की ओर से दायर आवेदन विचारणीय नहीं है और अपीलकर्ता द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार और बिना किसी साक्ष्य के हैं। उत्तरदाता अपने पति की उचित सेवा करने में सक्षम गृहिणी है और उसका आचरण और चरित्र अच्छा है। अपीलकर्ता सासाराम जिला परिषद का सदस्य है और वह एक पेट्रोल पंप चलाता है और उसका एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। जब उत्तरदाता-पत्नी ने आपत्ति की, तो उसके साथ क्रूरतापूर्वक मारपीट की गई और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। अपीलकर्ता का उसकी सहमति के बिना एक अन्य महिला के साथ अवैध संबंध है। अपीलकर्ता अपने सभी स्रोतों से 1,50,000/- रुपये प्रति माह कमाता है और उत्तरदाता 2013 से अपने मायके में रह रही है, लेकिन उसने उत्तरदाता को उसके भरण-पोषण के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। उत्तरदाता ने कभी भी ससुराल वालों को धमकी नहीं दी, न ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया, न ही अपमानित किया और न ही झगड़ा किया और उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, जिनका उद्देश्य उससे तलाक लेना है। इसलिए, तलाक की याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

6. मुकदमे की समाप्ति के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद ने माना कि अपीलकर्ता ने विवाह विच्छेद का कोई मामला नहीं बनाया है। अतः, तलाक की याचिका तदनुसार खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता-पति ने, विद्वान परिवार न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष तत्काल अपील दायर की।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि परिवार न्यायालय अपीलकर्ता के साथ हुई क्रूरता को समझने में विफल रहा है। उत्तरदाता एक झगड़ालू महिला है और वह स्वयं अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाना चाहती। उत्तरदाता

ने केवल अपीलकर्ता के किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया है, लेकिन उसने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। इसके बजाय, उत्तरदाता ने राज्य महिला आयोग, पटना के समक्ष मामला संख्या 257/2013 के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है और अपीलकर्ता के खिलाफ झूठे आरोपों के साथ दाउदनगर थाना मामला संख्या 336/2013 भी दायर किया है, जिसका उद्देश्य केवल अपीलकर्ता को परेशान करना, अपमानित करना और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। उत्तरदाता-पत्नी की गंभीरता इस तथ्य से स्पष्ट है कि तलाक के मामले में साक्ष्य के दौरान, उसने पति-पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए मामले को एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया। अपीलकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उत्तरदाता ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोई याचिका दायर नहीं की है। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि ये मुद्दे यह कहने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता को पारिवारिक दायरे में अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था और ये मुद्दे मानसिक यातना के अंतर्गत आते हैं और उत्तरदाता-पत्नी के हाथों क्रूरता क्रूरता की ओर ले जाते हैं।

8. उत्तरदाता-पत्नी के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि विद्वान परिवार न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से दायर तलाक याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है। तलाक याचिका में उत्तरदाता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप मनगढ़ंत, निराधार और बिना किसी सबूत के हैं। दरअसल, अपीलकर्ता के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और जब उसने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। अपीलकर्ता अपने सभी स्रोतों से 1,50,000/- रुपये प्रतिमाह कमा रहा है और उत्तरदाता 2013 से अपने मायके में रह रही है, लेकिन उसने उत्तरदाता को उसके भरण-पोषण के लिए एक पैसा भी नहीं दिया है। उत्तरदाता ने कभी भी ससुराल वालों को धमकी नहीं दी, न ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया, न ही अपमानित किया और न ही झगड़ा किया और उससे तलाक लेने के इरादे से उसके खिलाफ लगाए

गए सभी आरोप झूठे हैं।

9. अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के मद्देनजर, इस अपील में निर्धारण हेतु मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-

(i) क्या अपीलार्थी अपनी याचिका/अपील में मांगी गई राहत का हकदार है।

((ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय कानून की नजर में न्यायसंगत, उचित और टिकाऊ/मान्य है।

10. अपीलकर्ता ने वैवाहिक मामला संख्या 150/2021 में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की प्रार्थना की है।

11. जहाँ तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का सवाल है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसे चरित्र और आचरण की है जो दूसरे पति या पत्नी के मन में यह उचित आशंका पैदा करती है कि ओ.पी. उत्तरदाता के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने <u>समर घोष बनाम जया घोष के प्रमुख मामले, 2007 (4) एससीसी 511</u> में यह टिप्पणी की है कि एक पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। शिकायत किया गया व्यवहार और परिणामी खतरा या आशंका बहुत गंभीर, ठोस और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। विवाहित जीवन में होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़ा, सामान्य टूट-फूट, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

13. इस संदर्भ में, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा <u>नारायण गणेश</u>

दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने, एआईआर 1975, 1534 में रिपोर्ट किया गया, मामले में दिए गए निर्णय के दौरान की गई महत्वपूर्ण टिप्पणी को उद्धृत करना चाहते हैं। जो इस प्रकार है:-

> *"एक अन्य बात जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यद्यपि धारा 10(1) (ख) के तहत, याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, उचित होनी चाहिए, ऐसी आशंका के संदर्भ को छोड़कर, वैवाहिक संबंधों के निर्णय में लापरवाही के कानून के तहत ज्ञात एक उचित व्यक्ति की अवधारणा को लागू करना गलत है। पति-पत्नी से निस्संदेह अपेक्षा की जाती है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से चलाएँ, लेकिन क्रूरता के आरोप की जाँच करते समय न्यायालय का यह काम नहीं है कि वह विवाहित जीवन के तौर-तरीकों पर विचार करे। कोई व्यक्ति दिन भर का काम खत्म करने के लिए देर रात तक जागना चाहेगा और कोई व्यक्ति सुबह गोल्फ खेलने के लिए जल्दी उठना चाहेगा। न्यायालय इन लोगों की आदतों या शौक के आधार पर यह परीक्षण नहीं कर सकता कि क्या समान स्थिति वाला कोई समझदार व्यक्ति भी इसी तरह व्यवहार करेगा। "यह प्रश्न कि क्या शिकायत किया गया दुर्व्यवहार तलाक के लिए क्रूरता वगैरह है, मुख्य रूप से शिकायत करने वाले व्यक्ति पर इसके प्रभाव से निर्धारित होता है। प्रश्न यह नहीं है कि क्या आचरण एक समझदार व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदनशीलता वाले व्यक्ति के प्रति क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति/पत्नी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा।*
>
> *जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हँसाया*

जा सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में क्रूर नहीं हो सकता वह दूसरी परिस्थिति में अत्यधिक क्रूरता हो सकता है"। न्यायालय को एक आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई अस्तित्व में है) से नहीं, बल्कि उसके समक्ष उपस्थित विशेष पुरुष और महिला से निपटना होता है। आदर्श जोड़े या लगभग आदर्श जोड़े को शायद वैवाहिक न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि, भले ही वे अपने मतभेदों को स्पष्ट न कर पाएँ, लेकिन उनके आदर्श दृष्टिकोण उन्हें आपसी गलतियों और विफलताओं को नज़रअंदाज़ करने या उन पर पर्दा डालने में मदद कर सकते हैं।"

14. अपीलकर्ता-पति की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तथ्यों पर गौर करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदाता के क्रूर व्यवहार को ठोस, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार इस मामले में अपीलकर्ता-पति पर है, क्योंकि उसने उत्तरदाता के अपने प्रति क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक की राहत मांगी है। परिवार न्यायालय के समक्ष दायर वाद में कथित क्रूरता की विशिष्ट तिथि के संदर्भ में एक भी घटना का उल्लेख/आग्रह नहीं किया गया है। इसके अलावा, कथित तौर पर कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग कभी-कभी पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में दूसरे साथी को प्रतिशोध देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने का उचित/स्थायी आधार नहीं हो सकता। कुछ मामूली कथन या टिप्पणी या एक साथी द्वारा दूसरे को मात्र धमकी देना क्रूरता का ऐसा आदेश नहीं माना जा सकता, जो कानूनी तौर पर तलाक के आदेश के लिए आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में जन्मे और पले-बढ़े, अलग-अलग जीवन स्तर वाले, अलग-अलग

शैक्षणिक योग्यता वाले और जिस समाज में वे रहते हैं, उसमें अपनी स्थिति वाले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है।

15. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और उत्तरदाता के क्रूर व्यवहार के आदेश को तो और भी अधिक साबित कर पाया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के आदेश को मंजूरी देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

16. जहाँ तक परित्याग के आधार का प्रश्न है, अपीलकर्ता का मामला यह है कि उत्तरदाता के साथ अपीलकर्ता का विवाह 04.05.1984 को संपन्न हुआ था, लेकिन विवाह संबंध से कोई संतान नहीं है और उसने कई डॉक्टरों से परामर्श किया और बहुत पैसा खर्च किया ताकि उत्तरदाता से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके। हालाँकि, साथ ही, उसने यह भी कहा कि उसने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में उत्तरदाता के साथ 1-2 वर्ष बिताए थे, जो एक-दूसरे के विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। अपीलकर्ता का दावा है कि उत्तरदाता एक झगड़ालू महिला है और कई संबंधों में लिप्त है, लेकिन उसने इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाया है। अपीलकर्ता ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई याचिका भी दायर नहीं की है, जिससे यह तथ्य और भी पुष्ट होता है कि अपीलकर्ता ने उत्तरदाता को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है, जिससे तलाक याचिका में उसके आरोपों पर गंभीर संदेह पैदा होता है। इसी प्रकार, परित्याग के आधार पर भी, अपीलकर्ता तलाक की कोई डिक्री प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस प्रकार, अपीलकर्ता-पति यह साबित करने में विफल रहा है कि उत्तरदाता-पत्नी ने स्वयं अपीलकर्ता-पति को परित्यक्त किया है।

17."जगदीश सिंह बनाम माधुरी देवी", (2008) 10 एससीसी 497 में,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करते हुए, निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था और इसलिए न्यायालय के लिए न केवल विधि के प्रश्नों पर बल्कि तथ्यात्मक प्रश्नों पर भी विचार करना खुला था। यह स्थापित कानून है कि अपील मुकदमे की निरंतरता है। इस प्रकार अपील मुख्य मामले की पुनः सुनवाई है और अपीलीय न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य का "मौखिक और दस्तावेजी" रूप से पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा कर सकता है और अपने निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।

25. साथ ही, अपीलीय न्यायालय से अपेक्षा की जाती है, बल्कि बाध्य भी, कि वह मौखिक साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखे। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि विचारण न्यायालय के पास गवाहों के व्यवहार को देखने का एक लाभ और अवसर था, इसलिए, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को सामान्यतः प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। निस्संदेह, अपीलीय न्यायालय के पास मूल अदालत के समान ही शक्तियाँ हैं, लेकिन उनका प्रयोग उचित सावधानी, सतर्कता और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। जब विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर तथ्य का निष्कर्ष दर्ज किया गया हो, तो उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि साक्ष्य के मूल्यांकन में विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत या अनुचित न हो..."

18. विद्वान परिवार न्यायालय के संपूर्ण निर्णय को पढ़ने के बाद, ऐसा प्रतीत

होता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने में कोई गंभीर कानूनी त्रुटि या अवैधता नहीं है।

19. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई दम नहीं दिखता जिससे आक्षेपित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उचित हो। परिवार न्यायालय ने तलाक चाहने वाले अपीलकर्ता के वैवाहिक मामले को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

20. तदनुसार, वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है तथा आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की जाती है।

21. यदि कोई लंबित अं.आ. है तो उसका निपटारा किया जाता है।

(एस. बी. प्र. सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।